प्रदेश के कोटवारों के पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत की होगी वृद्धि

पांच एकड़ से कम भूमि वाले कोटवारों का बनेगा बीपीएल राशन कार्ड

रायपुर। किसी भी गांवों की सुरक्षा तथा वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना कोटवारों का जिम्मा होता है। राज्य शासन द्वारा कोटवार संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके मासिक पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कोटवारों के हितों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। पाण्डेय ने आज यहां बताया कि वर्तमान में जिन कोटवारों के पास सेवा भूमि नहीं है, उन्हें प्रति माह 3000 रूपए, जिनके पास तीन एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2700 रूपए और जिनके पास के पास तीन एकड़ से अधिक और 7.5 एकड़ तक सेवा भूमि है, उन्हें 2250 रूपए मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इसमें 50 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। पाण्डेय ने बताया कि ऐसे कोटवार जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उन्हें गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) का राशन कार्ड दिलाया जाएगा। जिन कोटवारों द्वारा मालगुजारी से प्राप्त भूमि स्वामी हक की भूमि को विक्रय कर दिया गया है, उस जमीन को शासकीय घोषित किया जाएगा और उन कोटवारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाएगी। इस संबंध में वर्ष 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे। राजस्व मंत्री ने बताया कि कोटवारों को उनके काम-काज के संबंध में तहसील एवं थाना में बुलाया जाएगा, लेकिन उनसे घरेलू कार्य नहीं कराया जाएगा। कोटवारों को प्रति वर्ष वर्दी के कपड़े देने एवं प्रत्येक तीन वर्ष में गरम कपड़े देने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। कोटवारों को उनकी सेवा भूमि में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। नक्सल हिंसा में मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने की दशा में कोटवारों को राज्य शासन के अनुग्रह अनुदान नियम 2013 के प्रावधानों के तहत राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अधिकार जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 की इस अधिसूचना के अनुसार नक्सल हिंसा में मृत्यु होने पर डेढ़ लाख रूपए और नक्सल हिंसा में शत-प्रतिशत स्थायी अपंगता होने पर 75 हजार रूपए देने का प्रावधान है।

पॉवर कंपनी की पहली महिला एमडी ने पदभार ग्रहण किया

कारबा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में प्रबंध निदेशक के पद पर तृप्ति सिन्हा की नियुक्ति की गई है। गुरुवार को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। स्टेट पॉवर कंपनी के इतिहास में तृप्ति सिन्हा पहली महिला एमडी हैं। इससे पहले वह स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने शासन की रीति-नीति के अनुरूप प्रदेश का पारेषण प्रणाली का उन्नत करने के लिए टीमवर्क के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रयास को अपनी प्राथमिकता बताया। तृप्ति सिन्हा ने वर्ष 1978 में बीई इलेक्ट्रिकल की उपाधि शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय जबलपुर से प्राप्त किया। 1979 में सहायक अभियंता, प्रशिक्षु के पद से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल भोपाल से अपने कैरियर की शुरूआत की।

शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट

3 युवक सहित अपचारी बालक हिरासत में

रायपुर। रावाभाठा सामुदायिक स्वास्थय केंद्र के पास तीन युवक सहित एक नाबालिग ने शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर युवक से मारपीट कर पेचकश से मारने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुरेश यादव पिता सुंदर यादव 19 वर्ष बुधवारी बाजार बीरगांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल रात प्रार्थी रावाभाठा के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र के पास खड़ा था तभी बीरगाव में रहने वाले आरोपी अंसुमन तिवारी पिता संतोश तिवारी 28 वर्ष, परवेज खान पिता तुफैल खान 20 वर्ष, किशोर उपाध्याय पिता दयानंद उपाध्याय 23 वर्ष व एक 16 वर्षीय नाबालिग प्रार्थी के पास आया और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। प्रार्थी द्वारा पैसा देने से इंकार करने पर आरोपियों ने प्रार्थी से मारपीट कर पेचकश से मारकर चोट पहुंचाए। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

कबीर जयंती 9 को, शहर में होंगे विविध आयोजन

रायपुर। ज्येष्ठ पूर्णमा एव कबीर जयंती के अवसर पर शहर में कबीर पंथी समाज द्वारा अनेक आयोजन किये जाने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार कबीर पंथी समाज द्वारा 9 जून को सुबह विधि विधान से पूजा अर्चन के साथ चौका आरती कर कबीर दास की पूजा की जाएगी। पूजा उपरात भक्तों के मध्य भंडारे का आयोजन भी किया ÷या है। समाज के सक्रिय सदस्य पदम लोचन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य समारोह रायपुर सहित बलौदा बाजार दामाखेड़ा, सारागांव एवं बिलाईगढ़ सरसींवा में आयोजित किया गया है।

पावर कंपनी आनलाइन भुगतान शुल्क लेना बंद करे : कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एम.ए. इकबाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में पूरे प्रदेश में 50 लाख से अधिक उपभोक्ता है जिनका मासिक बिल 400 से 500 करोड़ रूपये होता है। आनलाइन भुगतान में बिल की राशि में 1 से 1.5 प्रतिशत शुल्क के रूप में लिया जा रहा है जो कि गलत है कांग्रेस ऐसे शुल्क का विरोध करती है और इसे जनहित में बंद करने की मांग करती है। कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विभिन्न तरीको का उपयोग किया है। जिससे जनता की राहत देने का प्रावधान रखा गया है। परंतु देखने में यह आ रहा है कि बिजली बिल के आनलाइन भुगतान पर 1 से 1.5 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है। जबकि सरकार के अन्य विभागो जैसे टेलीफोन, बैंक की ई.एम.आई, आदि के आनलाइन भुगतान पर किसी प्रकार के शुल्क नही लिया जाता है। इस संबंध में पावर कंपनी के आला अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है। वैसे भी बिजली की बढ़ी दरो से आम उपभोक्ता परेशान है।

प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक

विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

रायपुर। प्रभारी मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में बाढ़ एवं नैसर्गिक आपदाओं से निपटने के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। सिंह ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में बाढ़ की सम्भावित स्थलों का चिन्हांकित कर सभी आवश्यक तैयारियां रखें और जिला और जनपद स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर सेना और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को सम्भावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित करने, मैदानी अधिकारियों को जलाशयों में जल स्तर बढ़ने और जल छोड़ने पर निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों का मरम्मत, जल मग्न होने वाले पुल के दोनों ओर रेडियम साईन बोर्ड लगाकर उस पर कंट्रोल रूम का नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग के अधिकारियों को बरसात के दौरान पहुंचविहीन राशन दुकानों में चार माह का खाद्य सामाग्री के अग्रिम भण्डारण करने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति में माहामारी की रोकथाम के लिए कम्बेट टीम गठित करने, प्राथमिक-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध कराने और पहुंचविहीन गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन माह के लिए क्लोरिन की गोली एवं ओआरएस पैकेट प्रदाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्त्रोतों का शुद्धिकरण और पानी टंकी एवं नालियों की साफ-सफाई के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव रेणु पिगे ने प्रस्तुतिकरण के जरिये प्रदेश में मानसून आने के पहले संभावित बाढ़ से निपटने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण, बाढ़ से राहत एवं बचाव संबंधित उपकरणों को तैयार रखने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और नालियों की सफाई कराने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है। इसके लिए जिलों को 97 करोड़ रूपए के अनुदान भी जारी कर दिए गए है। बैठक में प्रमुख सचिव वन आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव वित्त अमिताभ जैन, सचिव जल संसाधन गणेश शंकर मिश्रा, सचिव गृह अरूण देव गौतम, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण पी.सी. मिश्रा, सचिव कृषि अनूप वास्तव, सचिव ऊर्जा आशीष भट्ट, सचिव आवास एवं पर्यावरण संजय शुक्ला, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड गिरधारी नायक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने वालों पर पुलिस करेगी चालान

बिलासपुर। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट-बीड़ी का सेवन करने वालों पर अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस को चालान बुक उपलब्ध करा दिया है। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोटपा एक्ट के तहत 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बिलासपुर में कोटपा अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन कराने का लक्ष्य रखा गया है। अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना अपराध है। अब जिला प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाए÷ा। इसके लिए पुलिस विभाग को निर्देश के साथ चालान बुक भी उपलब्ध करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश है कि होटल व अन्य संस्थानों के अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपए का चालान किया जाएगा। इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की योजना बना ली है। एक सप्ताह के भीतर टीम शहरी क्षेत्र में कार्रवाई शुरू कर देगी। **अब तक 65 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई :** कोटपा एक्ट के तहत 27 मई से अब तक 65 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बड़े होटल, रेस्टोरेंट के अलावा दुकान, पान ठेले आदि में धूम्रपान निषेध का बोर्ड नहीं लगाने का चालान किया गया। **सिगरेट जलाने के लिए नहीं मिलेगा लाइटर :** अधिनियम के अनुसार पान ठेला, दुकानों में सिगरेट खरीदी करने के बाद लाइटर, माचिस, ऐश ट्रे आदि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ऐसे करने पर भी दुकानदार के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानने पर पुलिस प्रकरण दर्ज करेगी। कोटपा एक्ट 2003 को प्रभावी ढंग से लागू करने लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। पुलिस के जवान ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 200 रुपए जुर्माना करेंगे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से क्लर्क की मौत

अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निमोरा के पास हुआ हादसा

रायपुर। ग्राम निमोरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अंबिकापुर निर्वाचन कार्यालय के क्लर्क की मौत हो गई। वहीं उसके साथी को घायल अवस्था में उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम निमोरा स्थित प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग लेने आए 5 अधिकारी कल रात खाना खाकर टहलने निकले। उसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने दो अधिकारियों को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे गंभीर रूप से घायल अंबिकापुर निर्वाचन कार्यालय के क्लर्क अनिल कुश्वाहा 33 वर्ष व मेघनाथ माली 36 वर्ष को तत्काल आंबेडकर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत अनिल कुश्वाहा को मृत घोषित कर दिया। वहीं मेघनाथ माली की अस्पताल में ईलाज जारी है।

नारायणपुर के एडिशनल कलेक्टर संतोष देवांगन को 7 साल की कैद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के एडिशनल कलेक्टर संतोष देवांगन को भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को 7 साल की कैद और डेढ़ लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है। एसीबी की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। गौरतलब हो कि बिलासपुर में एसडीएम रहे संतोष देवांगन ने पूर्व एसडीएम संजय अग्रवाल के आदेश में कूटरचना कर बिल्डर चितपाल वालिया को लाभ पहुंचाया था। पूर्व एसडीएम संजय अग्रवाल द्वारा अवैध कब्जे की जमीन का प्लाटिंग करने वाले एक बिल्डर पर किये डेढ़ लाख के जुर्माना राशि को बिल्डर से मिलीभगत कर 15 हजार रुपये कर दिया था जिसकी शिकायत कमलेश शुक्ला और सरदारी लाल ने एसीबी में की थी। एसीबी ने इस मामले में करीब दो साल पूर्व उन्हें बलौदाबाजार से भी गिरफ्तार किया था, हालांकि जमानत पर वे रिहा हो गए थे। आज मामले की सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत में की गई। इस अवसर पर एडीएम भी मौजूद थे। सुनवाई में संतोष देवांगन को दोषी पाते हुए अदालत ने उन्हें 7 साल की कैद और डेढ़ लाख रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।

मामूली बात पर युवक से मारपीट

रायपुर। घर के पास लघुशंका करने से मना करने पर युवक से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अजय चौधरी पिता स्व.कपिलदेव चौधरी 49 वर्ष हीरा मार्केट के पास पण्डरी का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल रात आरोपी लोकनाथ जांगड़े अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रार्थी के घर के पास लघुशंका कर रहे थे। जिससे प्रार्थी ने मना किया तो आरोपियों ने प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किए। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

महिला से छेड़खानी, जुर्म दर्ज

रायपुर। ग्राम सिवनी में दो युवक द्वारा एक महिला के घर जबरन प्रवेश कर छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर मुजगहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सिवनी निवासी 26 वर्षीय प्रार्थिया ने कल रात थाने में शिकायत किया कि गांव में ही रहने वाले आरोपी गेंदलाल जांगड़े व तारण जांगड़े जबरन प्रार्थिया के घर में आए और प्रार्थिया को बेईज्जत करने के नियत से हाथ बांह पकड़ा। प्रार्थिया द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट किया। प्रार्थिया की शिकायत पर मुजगहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 456, 354,323,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

मनरेगा में काम कर रहे मजदूर की मौत

घटना डभरा थाना क्षेत्र के नवापारा गांव की

तालाब गहरी करण के दौरान हुई मौत

जांजीर चांपा। डभरा ब्लाक के नवापारा गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई । मृतक का उमाशंकर 50 वर्ष नवापारा निवासी बताया जा रहा है। आज सुबह नवापारा गांव के तलाब गहरी करण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा था जिसमें सैकड़ो मजदुर कार्य में लगे हुऐ थे। तभी मृतक उमाशंकर के सीने में दर्द होने लगा जिससे वह बेहोश हो कर गिर गया। आनन फानन में साथ में काम कर रहे लोग डभरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ समय बाद उमाशंकर के मौत हो गई । पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मृतक के शव का पंचनामा का पीएम कराया गया। जहां डांक्टरो ने बताया की उमाशंकर की मौत हृदयगति रोकने से हुई। उधर तलाब गहरीकरण मे काम कर रहे अन्य मजदूरो ने ग्राम पंचायत के अधिकारीयों पर अरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत कार्य कर रहे लोगो को किसी प्रकार की सुरक्षा की सुविधा नही दी जाती और न पंचायत द्वारा किसी प्रकार की राहत दी जाती । मृतक उमाशंकर की भी जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार हुआ रहता तो उनकी मौत नही हुई रहती है। इस प्रकार मजदूरो ने ग्राम पंचायत के अधिकारीयों पर मौत पर गैरजिम्मेदारी रैवया अपनाने का आरोप लगाया है। वही पुलिस शव का पंचनामा कर मृतक के मौत की अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

12 नये ओव्हर ब्रिज और अण्डर ब्रिजों का होगा निर्माण

रायपुर। राज्य में सुगम आवागमन के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वर्ष बारह नये रेल्वे ओव्हर ब्रिज और अण्डर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने आज यहां बताया कि इनके निर्माण के लिए चालू वर्ष 2017-18 के बजट में 91 करोड़ 91 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इनमें जिला जांजगीर-चांपा के नैला-चांपा हावड़ा मुम्बई रेल्वे लाईन पर पांच करोड़ रूपए से रेल्वे अण्डर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। जिला मुख्यालय रायगढ़ के दोनों ओर कोतरा रोड़ पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण पांच करोड़ रूपए और हावड़ा मुम्बई रेलमार्ग के लेबल क्रासिंग (चक्रधर नगर) में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण पांच करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा। इसी तरह मुम्बई-हावड़ा रेलमार्ग के लेबल भाठापारा समीप सिद्धबाबा (दौराभाठा) गेट के रेल्वे क्रासिंग और मुम्बई-हावड़ा रेलमार्ग के हथबंध के समीप के रेल्वे क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण के लिए छह-छह करोड़ रूपए का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ से लगभग पांच सौ तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जायेंगे

रायपुर। विगत दिनों रायपुर (चौपाल) निवास अशोक बजाज के निवास रायपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पश्चात कैलाशमान सरोवर यात्रा कमेटी की बैठक संपन्न हुई जिसमें सैकड़ों तीर्थ यात्री शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से अशोक बजाज को कमेटी का संरक्षक चुना गया। प्रस्तावक कुबर राम सपहा ने प्रस्ताव रखा जिसे सदस्य ने तालियों की ध्वनिमत से प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया। अशोक बजाज ने कहा कि हम रायपुर छत्तीसगढ़ से लगभग 500 तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए लक्ष्य बनाया है जिस पर 500 तीर्थयात्रियों का प्रस्ताव राज्य शासन और केन्द्रशासन से यात्रियों को यात्रा कराने के लिए पैकेज की मांग रखी जायेगी और 500 यात्रियों का तीर्थयात्रा का लक्ष्य को मूर्तिरूप दिया जायेगा। अशोक बजाज ने कमेटी का प्रदेश संयोजक के रूप में कुबेर राम सपहा को आगामी आदेश तक नियुक्त किया है और मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी अतिरिक्त रूप से कुबेर राम सपहा को दिया गया है आगामी 11 जून से रमन गोठ कार्यक्रम के पश्चात मानसरोवर तीर्थ यात्रियों का फार्म पंजीयन किया जायेगा और फार्म भरवाएं जायेंगे। यात्रियों में किशोर यादव (गवली) रायपुर को कमेटी का रायपुर शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है 11 जून से यात्रियों की पंजीयन एवं डॉक्टरी परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। समाचार मीडिया को यह जानकारी कुबेर राम सपहा ने दिया है।

सिंघानिया बिल्डकॉन एवं बेबीलॉन ग्रुप में आयकर की जांच लगभग पूरी, करोड़ों की गड़बड़ी मिली

-सिंघानिया की 10 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी
-बेबीलॉन में एक्सटेंशन के लिए विदेश से इन्वेस्टमेंट

रायपुर। राजधानी के सिंघानिया बिल्डकॉन और बेबीलॉन ग्रुप में आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच कार्यवाही लगभग पूरी हो गई है। दोनों ग्रुप से करोड़ों की गड़बड़ी पकड़ी गई है। सिंघानिया बिल्डकॉम की जहां 10 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है, वहीं बेबीलॉन ग्रुप में एक्सटेंशन के लिए विदेश से डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आयकर विभाग की अलग-अलग टीम ने सिंघानिया बिल्डकॉन और बेबीलॉन होटल ग्रुप में छापा मारा है। इस कार्यवाही के दौरान दोनों ग्रुप में जांच-पड़ताल की जा रही थी आज लगभग दोनों जगह जांच कर ली गई है। आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर केसी घुमारिया के मुताबिक सिंघानिया बिल्डकॉन में अब तक छापेमारी में करीब 10 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर बेनामी कंपनियां खोल रखी है। अलग-अलग जगहों पर इन्वेसटमेंट के भी दस्तावेज मिले हैं जिस पर अभी जांच चल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अकाउंट मिले हैं जिसमें रखे पैसे की जानकारी नहीं मिल पायी। हैरानी की बात ये है कि उन्हीं बेनामी बैंक एकाउंट के आधार पर ही लोन लिया जाता था। श्री घुमारिया ने बेबीलॉन होटल में जांच के बारे में बताया कि होटल के खाते में विदेश से 2 करोड़ के इंडियन रूपए वेल्यु के डॉलर जमा कराये गये थे। उसी रकम से होटल के पार्किंग के लिए जमीन खरीदी गयी और पार्किंग बनाया गया है। पार्किंग की जमीन ज्यादा रकम में खरीद कर कम में बतायी गई है। आयकर अधिकारी ने के अनुसार इसकी भी जांच चल रही है। इसके अलावा हॉल बुकिग में 6 करोड़ की गड़बड़ी सामने आयी है। इस रकम की एंट्री बिल में नहीं है। बताया गया है कि आज रात तक जांच पूरी कर ली जाएगी।

नदियों, जलाशयों का जलस्तर घटा, खेतों में पड़ने लगी दरारें

किसानों को अब मानसून का इंतजार

रायपुर। भीषण गर्मी के साथ मई माह भी समाप्त हो गया है और जून माह की शुरूआत हो चुकी है, लेकिन मानसून को छग आने में अभी सप्ताहभर या उससे अधिक दिन भी लग सकते है। ऐसे में किसानों की चिंता लगाकर बढ़ रही है। भीषण गर्मी के चलते कई किसानों के खेतों में दरारे पड़नी शुरू हो गई है ऐसे में अगर मानसून का समय पर प्रदेश में आगमन नहीं हुआ तो किसानों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पिछले दो वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के कई तहसील सूखे की चपेट में आ सकते है। भीषण गर्मी के चलते इस बार प्रदेश की नदियां, जलाशयो व तालाबों का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसका असर ना केवल प्रदेश की जनता पर बल्कि उद्योगों एवं किसानों पर भी पड़ रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरे दिखने लगी है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और नदियों व जलाशयों का पानी स्तर काफी नीचे चला गया है उसके बाद किसानों को इंतजार है तो बस मानसून का। समय पर मानसून के नहीं आने से किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। गर्मी के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसानों के खेत सूखकर उनमें दरारे आने लगी है। ऐसे में अगर बारिश जल्द ही शुरू नहीं हुई तो उन किसानों को सूखा जैसे बड़े संकट से जूझना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि पिछले दो वर्ष में प्रदेश में कमजोर मानसून के चलते सैकड़ों किसानों के खेत सूखे पड़े रहे। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की मदद से सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने हुए उन्हें राहत पहुंचाई गई। लेकिन इसके बावजूद पिछले दो वर्षों में कमजोर मानसून को देखते हुए इस बार भी किसानों की चिंता बढ़ी हुई है।

बालको सी.ई.ओ. ने ग्रहण किया लीडर्स अवार्ड

कारबा। सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए बालको ने वर्ष 2017 का 'लीडर्स अवार्ड जीता। मेगा बिजनेस श्रेणी में बालको को यह पुरस्कार फ्रास्ट एंड सुलिवन तथा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) सस्टेनेबिलिटी 4.0 अवाड्‌र्स 2017 की ओर से प्रदान किया गया।